भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1517

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: काजू और गन्ना किसानों को सहायता

1517. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गोवा में छोटे और मध्यम काजू बागान मालिकों और गन्ना उत्पादकों के सामने आने वाले वित्तीय संकट, विशेषकर बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव, उच्च आदान लागत, श्रमिकों की कमी और संस्थागत सहायता की कमी के कारण, का कोई आकलन किया है या प्राप्त किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार गोवा के काजू उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद तंत्र या समर्पित सहायता शुरू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो गोवा में काजू क्षेत्र की निरंतर नीतिगत उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार संजीवनी शुगर फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फैक्ट्री, कामगारों के लिए प्रस्तावित विकल्प क्या हैं और भूमि के उपयोग की योजना क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी नहीं।

(ख): जी नहीं। वर्तमान में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के अंतर्गत और अधिक फसलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, शीघ्र खराब नहीं होने वाली, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, व्यापक उपभोग की वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक आदि शामिल हैं।

तथापि , सरकार ने काजू उद्योग के लिए कई पहल की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे काजू सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच योजना के अंतर्गत आते हैं।

ii. एमआईडीएच के तहत काजू के विकास के कार्यक्रम काजू और कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। निदेशालय देश में उच्च उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करके नए रोपण कार्यक्रम और जीर्णोद्धार के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रमों में स्थान की उपयुक्तता के अनुसार जीर्ण-शीर्ण बागानों को हटाना और उच्च उपज देने वाली किस्मों के साथ पुनः रोपण शामिल है।

iii. काजू और कोको विकास निदेशालय विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के सहयोग से विभिन्न प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

(ग): केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 में चीनी उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया था। इसके बाद, कोई भी उद्यमी देश के किसी भी हिस्से में चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक निजी क्षेत्र का संबंध है, बंद या निष्क्रिय चीनी मिलों को पुनः खोलने/पुनरुद्धार करने के लिए कदम उठाना संबंधित उद्यमियों की ज़िम्मेदारी है। सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के मामले में, इस दिशा में उचित कदम उठाना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है। केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की चीनी मिल स्थापित नहीं करती है।

*****